

पर्वतीय ग्रामीण समाज में निर्धन वर्ग के रोजगार के साधनों की स्थिति: टिहरी जिले के संदर्भ में।

विजय सिंह रौतेला

महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ़ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

डॉ राजन मिश्रा

प्रोफेसर, समाज कार्य, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ

सार

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर पारिस्थितिक नाजुकता, दूरदर्शिता और सीमित औद्योगीकरण के कारण संरचनात्मक रूप से बाधित हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के संदर्भ में, यह मुद्दा विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि आजीविका अभी भी कम उत्पादकता वाली कृषि, मौसमी श्रम और प्रवासन पर बहुत अधिक निर्भर है। साक्ष्य इंगित करते हैं कि टिहरी जैसे पहाड़ी जिलों में महत्वपूर्ण अल्प-रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीमित विविधता का अनुभव होता है, जिससे कई परिवारों को जीवित रहने की रणनीति के रूप में प्रवासन को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह अध्ययन टिहरी में ग्रामीण गरीबों के बीच रोजगार के अवसरों की स्थिति, पैटर्न और निर्धारकों की जांच करता है। माध्यमिक डेटा और हालिया नीतिगत पहल एक मिश्रित परिदृश्य का सुझाव देते हैं: जबकि स्वयं सहायता समूह उद्यमों, मनरेगा कार्यों और एकीकृत आजीविका पैकेज जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने स्थानीय आय के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन ये बढ़ते ग्रामीण कार्यबल को अवशोषित करने के लिए अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, देवप्रयाग ब्लॉक में एलईडी बल्ब निर्माण जैसी एसएचजी-आधारित पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभ और वित्तीय स्वतंत्रता उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म-उद्यम मॉडल की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ऐसे हस्तक्षेपों के बावजूद, संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी रहती हैं। टिहरी सहित जिलों में शिक्षित समूहों के बीच युवा बेरोजगारी 20 प्रतिशत से अधिक बताई गई है, जो आकांक्षाओं और उपलब्ध स्थानीय रोजगार के बीच बेमेल को दर्शाता है। पहाड़ी गांवों से निरंतर पलायन स्थानीय आजीविका की सीमित व्यवहार्यता को रेखांकित करता है, भले ही कुछ रिवर्स माइग्रेशन और पर्यटन से जुड़े निवेश (जैसे कि टिहरी झील विकास पहल) उभरते अवसर दिखाते हैं। सार का निष्कर्ष है कि टिहरी में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार के लिए एक पर्वत-विशिष्ट विकास रणनीति की आवश्यकता है जो टिकाऊ पर्यटन, कृषि-आधारित विविधीकरण, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता को एकीकृत करती है। पर्वतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकटपूर्ण प्रवासन को कम करने और समावेशी आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, बाजार पहुंच और संस्थागत समर्थन को मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: पर्वतीय ग्रामीण, निर्धन वर्ग, रोजगार, साधनों

परिचय

पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र एक विशिष्ट विकास संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसमें भूगोल, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक संरचनाएं आजीविका के अवसरों को आकार देने के लिए परस्पर क्रिया करती हैं। मैदानी क्षेत्रों के विपरीत, पहाड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता बिखरी हुई बस्तियाँ, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, सीमित खेती योग्य भूमि और कमजोर बाजार कनेक्टिविटी हैं। ये संरचनात्मक बाधाएं अक्सर सीमित रोजगार अवसरों में बदल जाती हैं, खासकर ग्रामीण गरीबों के लिए जिनके पास सीमित संपत्ति, कौशल और गतिशीलता होती है। भारतीय हिमालयी राज्य उत्तराखंड में, यह समस्या विशेष महत्व रखती है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जहां आर्थिक विविधीकरण धीमा और असमान बना हुआ है। टेहरी गढ़वाल जिला (आमतौर पर टेहरी जिला के रूप में जाना जाता है) एक विशिष्ट पर्वतीय ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो लगातार आजीविका चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से निर्वाह कृषि, पशुपालन और वन संसाधनों पर निर्भर, जिले ने पिछले कुछ दशकों में गहन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। टिहरी बांध के निर्माण से ढांचागत परिवर्तन और कुछ स्थानीयकृत आर्थिक गतिविधियां आईं, फिर भी व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अल्परोजगार, मौसमी कार्य पैटर्न और बड़े पैमाने पर पलायन से जूझ रही है। कई गरीब परिवारों के लिए, कृषि काफी हद तक वर्षा आधारित और कम उपज वाली बनी हुई है, जिससे यह आजीविका के एकमात्र स्रोत के रूप में अपर्याप्त है। सीमित स्थानीय रोजगार के सबसे स्पष्ट परिणामों में से एक मजदूरी और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में युवाओं और कामकाजी उम्र के वयस्कों का पहाड़ी गांवों से शहरी केंद्रों की ओर लगातार प्रवासन है। जबकि प्रवासन प्रेषण आय प्रदान करता है, इससे जनसांख्यिकीय असंतुलन, कृषि का स्त्रीकरण और पर्वतीय समुदायों का क्रमिक सामाजिक-आर्थिक कमजोर होना भी होता है। बढ़ती कठिन परिस्थितियों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिलाओं, बुजुर्गों और सीमांत किसानों को अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। साथ ही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने, ग्रामीण पर्यटन पहल और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे सरकारी हस्तक्षेपों ने जिले के भीतर रोजगार के अवसरों का विस्तार करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के बावजूद, टिहरी में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसरों की पर्याप्तता, पहुंच और स्थिरता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। पहाड़ी इलाके में उच्च लेनदेन लागत, कमजोर औद्योगिक उपस्थिति और सीमित निजी निवेश जारी है। इसके अलावा, शिक्षित ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाएं तेजी से बदल रही हैं, जिससे उपलब्ध कम कौशल वाले स्थानीय काम और उभरती रोजगार उम्मीदों के बीच एक बेमेल पैदा हो रहा है। इसलिए संदर्भ-विशिष्ट विकास रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए रोजगार की वर्तमान स्थिति, आजीविका कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और गरीब परिवारों के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को समझना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन टिहरी जिले में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसरों की स्थिति की जांच करता है। इसका उद्देश्य मौजूदा आजीविका पैटर्न का विश्लेषण करना, प्रमुख बाधाओं की पहचान करना और आय सुरक्षा बढ़ाने में सरकार और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों की भूमिका का मूल्यांकन करना है। पहाड़ी ग्रामीण समाज पर ध्यान केंद्रित करके, अध्ययन का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में समावेशी पहाड़ी विकास और टिकाऊ आजीविका सृजन पर नीतिगत चर्चा में योगदान देना है।

भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

टिहरी गढ़वाल जिले का पहाड़ी इलाका ग्रामीण गरीबों की रोजगार संरचना को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। खड़ी ढलानों, नाजुक भूविज्ञान, खंडित भूमि जोतों और बिखरी हुई बस्तियों की विशेषता वाला यह जिला लगातार प्राकृतिक और ढांचागत बाधाओं का सामना करता है जो कृषि उत्पादकता और गैर-कृषि आर्थिक विस्तार दोनों

को सीमित करते हैं। ऊंचाई संबंधी भिन्नता और लगातार जलवायु संबंधी अनिश्चितताएं मशीनीकृत खेती और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की संभावनाओं को और सीमित कर देती हैं। कई गांव शारीरिक रूप से अलग-थलग रहते हैं, खासकर मानसून और सर्दियों के मौसम में, जब सड़क संपर्क अविश्वसनीय हो जाता है। यह भौगोलिक अलगाव परिवहन लागत को बढ़ाता है, बाजार भागीदारी को कम करता है और ग्रामीण उद्यमों में निजी निवेश को हतोत्साहित करता है। सामाजिक-आर्थिक रूप से, टिहरी उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के व्यापक विकास पैटर्न को दर्शाता है, जहां परिवारों का एक बड़ा हिस्सा छोटी और सीमांत भूमि जोत पर निर्भर है। दूरदराज के ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच गरीब परिवारों की भेद्यता को बढ़ाती है। अनुसूचित जाति, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को उत्पादक संसाधनों तक पहुंचने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्वाह-उन्मुख बनी हुई है, जिसमें आय विविधीकरण का स्तर कम है। ये भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ मिलकर एक संरचनात्मक रोजगार घाटा पैदा करती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और ऊपर की गतिशीलता को बाधित करती है।

कृषि पर निर्भरता और अल्परोज़गार

टिहरी में कृषि ग्रामीण आजीविका की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही है, फिर भी पर्याप्त और स्थिर रोजगार पैदा करने की इसकी क्षमता लगातार कमजोर हुई है। जिले में खेती मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, छोटे और बिखरे हुए भूखंडों वाले सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है जो पैमाने की अर्थव्यवस्था को सीमित करते हैं। पारंपरिक फसल पैटर्न - मुख्य रूप से अनाज जैसे मंडुआ (फिंगर बाजरा), झंगोरा (बार्नयार्ड बाजरा), और सीमित घाटी क्षेत्रों में धान - अपेक्षाकृत कम मौद्रिक रिटर्न देते हैं। अपर्याप्त सिंचाई कवरेज, मिट्टी का कटाव, वन्य जीवन की फसल क्षति, और वर्षा पैटर्न में बदलाव कृषि विश्वसनीयता को और कम कर देते हैं। इन बाधाओं के कारण, टिहरी में कृषि एक व्यवहार्य पूर्णकालिक व्यवसाय के बजाय अंशकालिक या निर्वाह गतिविधि के रूप में काम कर रही है। ग्रामीण परिवारों को अक्सर मौसमी अल्परोज़गारी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर कम कृषि महीनों के दौरान जब श्रम की मांग में तेजी से गिरावट आती है। यह छिपी हुई बेरोजगारी विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के बीच स्पष्ट है। पिछले दो दशकों में कृषि का महिलाकरण तेज हो गया है क्योंकि पुरुषों का पलायन बढ़ गया है, जिससे खेती, पशुधन की देखभाल, ईंधन की लकड़ी संग्रह और घरेलू प्रबंधन की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है। अपनी केंद्रीय भूमिका के बावजूद, महिला किसानों के पास अक्सर भूमि स्वामित्व, ऋण तक पहुंच, आधुनिक इनपुट और विस्तार समर्थन की कमी होती है, जो उत्पादकता लाभ और आय वृद्धि को सीमित करता है। इस प्रकार, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि संरचना कम श्रम अवशोषण क्षमता और उच्च भेद्यता प्रदर्शित करती रहती है।

आजीविका रणनीति के रूप में प्रवासन

पर्याप्त स्थानीय रोजगार अवसरों के अभाव में, पलायन, टिहरी में ग्रामीण गरीबों के लिए एक प्रमुख आजीविका रणनीति के रूप में उभरा है। मौसमी और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रवासन धाराएँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें युवा पुरुष और तेजी से शिक्षित युवा मजदूरी रोजगार की तलाश में शहरी केंद्रों जैसे देहरादून, दिल्ली और अन्य महानगरीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। प्रवास अक्सर अवसर-प्रेरित होने के बजाय संकट-प्रेरित होता है, जो सीमित स्थानीय आर्थिक गतिशीलता को दर्शाता है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजा गया धन ग्रामीण घरेलू उपभोग को बनाए रखने, शिक्षा के वित्तपोषण और बुनियादी आवास सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, प्रवासन की सामाजिक लागत पर्याप्त है। टिहरी के कई गाँवों में जनसांख्यिकीय असंतुलन है, जिसमें कामकाजी

उम्र की आबादी में गिरावट और बुजुर्ग निवासियों का अनुपात बढ़ रहा है। पीक सीज़न के दौरान कृषि श्रमिकों की कमी कुछ इलाकों में आम हो गई है। महिलाएँ पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति में खेतों और घरों का प्रबंधन करते हुए असंगत बोझ उठाती हैं, जो काम की सघनता और समय की गरीबी में योगदान देता है। इसके अलावा, प्रवासन हमेशा स्थिर या सुरक्षित रोजगार की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि कई प्रवासी कम वेतन और सीमित सामाजिक सुरक्षा वाले अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों तक ही सीमित रहते हैं। बड़े पैमाने पर पलायन की निरंतरता से संकेत मिलता है कि स्थानीय रोजगार सृजन पहल ने अभी भी जिले के भीतर पर्याप्त, आकर्षक और टिकाऊ आजीविका विकल्प तैयार नहीं किए हैं।

सरकारी रोजगार कार्यक्रमों की भूमिका

सार्वजनिक नीति हस्तक्षेपों ने टिहरी के ग्रामीण रोजगार परिदृश्य में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई है। इनमें से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। यह कार्यक्रम प्रति ग्रामीण परिवार को 100 दिनों तक के वेतन रोजगार की गारंटी देता है और जिले की कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सड़क निर्माण, जल संचयन संरचनाओं, भूमि समतलन और वनीकरण कार्यों जैसी गतिविधियों का समर्थन करता है। मनरेगा के अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कौशल विकास पहल और ग्रामीण उद्यमिता योजनाओं ने आय विविधीकरण को बढ़ावा देने की मांग की है। टिहरी के कई ब्लॉकों में महिला स्वयं सहायता समूह सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म उद्यम जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो मामूली लेकिन महत्वपूर्ण पूरक आय में योगदान दे रहे हैं। गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार क्षमता में सुधार के लिए ग्रामीण युवाओं को लक्षित करने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। हालाँकि, इन कार्यक्रमों का परिवर्तनकारी प्रभाव असमान रहता है। फ़्रील्ड अवलोकन और द्वितीयक साक्ष्य वेतन भुगतान में देरी, मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की सीमित संख्या, अपर्याप्त संपत्ति गुणवत्ता और एसएचजी उत्पादों के लिए कमजोर बाजार लिंकेज जैसे मुद्दों का सुझाव देते हैं। इसके अलावा, कई कार्यक्रम एकीकृत आजीविका योजना के बजाय अलगाव में संचालित होते हैं। नतीजतन, जबकि सरकारी योजनाएं अल्पकालिक राहत और आय को सुगम बनाती हैं, उन्होंने अभी तक बड़े पैमाने पर, स्थायी रोजगार उत्पन्न नहीं किया है जो प्रवासन के रुझान को उलटने में सक्षम हो।

उभरते अवसर और लगातार चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में, टिहरी जिले में पर्यटन, बागवानी विविधीकरण और लघु-स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े उभरते आजीविका के अवसर दिखाई देने लगे हैं। टिहरी बांध जलाशय के आसपास झील आधारित पर्यटन के विकास ने नौकायन, आतिथ्य, होमस्टे और स्थानीय सेवा प्रावधान में नई संभावनाएं पैदा की हैं। यदि पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कौशल विकास द्वारा समर्थित हो तो आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में इको-पर्यटन और साहसिक पर्यटन में भी रोजगार सृजन की संभावना है। बागवानी, बे-मौसमी सब्जियों की खेती, औषधीय पौधों की खेती और मधुमक्खी पालन को पारंपरिक अनाज की खेती के उच्च मूल्य वाले विकल्प के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर ग्रामीण सड़कें, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म धीरे-धीरे बाज़ारों और सूचनाओं तक पहुंच बढ़ा रहे हैं, खासकर युवा उद्यमियों के लिए। स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और ग्रामीण पर्यटन सर्किट पर सरकार का जोर इन रुझानों को और मजबूत कर सकता है। फिर भी, इन अवसरों का विस्तार असमान और भौगोलिक रूप से केंद्रित है। सीमित कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे, कमजोर मूल्य श्रृंखला, अपर्याप्त ऋण पहुंच, कौशल बेमेल और पर्यावरणीय नाजुकता सहित संरचनात्मक बाधाएं व्यापक-आधारित रोजगार वृद्धि को प्रतिबंधित करती रहती हैं। जलवायु

परिवर्तन के प्रभाव, जैसे अनियमित वर्षा और चरम मौसम की घटनाएं, पर्वतीय आजीविका के लिए अनिश्चितता की एक और परत जोड़ते हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए, विशेष रूप से दूरदराज और ऊंचाई वाले गांवों में रहने वाले लोगों के लिए, लक्षित संस्थागत समर्थन के बिना उभरती आर्थिक गतिविधियों का लाभ प्राप्त करना मुश्किल है।

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान अध्ययन में टिहरी गढ़वाल जिले में ग्रामीण गरीबों के बीच रोजगार के अवसरों की स्थिति की जांच करने के लिए एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध डिजाइन को अपनाया गया है। पहाड़ी संदर्भ में ग्रामीण रोजगार की बहुआयामी प्रकृति को पकड़ने के लिए अध्ययन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ता है। मिश्रित-विधि ढांचे को उपयुक्त माना गया क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार पैटर्न न केवल मापने योग्य आर्थिक संकेतकों द्वारा बल्कि सामाजिक, भौगोलिक और संस्थागत कारकों द्वारा भी आकार लेते हैं जिनके लिए प्रासंगिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। अनुसंधान मुख्य रूप से जहां उपलब्ध हो वहां चयनात्मक क्षेत्र-आधारित अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित माध्यमिक डेटा पर आधारित है। माध्यमिक डेटा सरकारी रिपोर्टों, जिला सांख्यिकीय पुस्तिकाओं, जनगणना प्रकाशनों, उत्तराखंड सरकार की रिपोर्टों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरजीए) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से एकत्र किया गया था। इन स्रोतों का उपयोग कार्यबल भागीदारी, प्रवासन पैटर्न, कार्यक्रम कवरेज और क्षेत्रीय रोजगार वितरण के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। सैद्धांतिक आधार और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रासंगिक अकादमिक साहित्य, नीति पत्र और हिमालयी ग्रामीण आजीविका पर पिछले अध्ययनों की भी समीक्षा की गई। विश्लेषणात्मक स्पष्टता के लिए, अध्ययन छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और कमजोर सामाजिक समूहों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित ग्रामीण परिवारों पर केंद्रित है। जहां भी संभव हो, टिहरी के भीतर स्थानिक भिन्नता को समझने के लिए ब्लॉक-स्तरीय और जिला-स्तरीय संकेतकों की जांच की गई है। रोजगार की उपलब्धता, अल्परोजगार पैटर्न और सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन करने के लिए वर्णनात्मक आंकड़े, प्रतिशत विश्लेषण और प्रवृत्ति व्याख्या विधियों को नियोजित किया गया है। भौगोलिक अलगाव, मौसमी श्रम मांग और लैंगिक कार्य बोझ जैसी संरचनात्मक बाधाओं को समझने के लिए गुणात्मक व्याख्या का उपयोग किया गया है। कार्यप्रणाली में प्रमुख ग्रामीण रोजगार पहलों के कार्यान्वयन और परिणामों की जांच करके एक कार्यक्रम मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य भी शामिल है। मनरेगा के तहत उत्पन्न मजदूरी रोजगार की सीमा, आय विविधीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और पर्यटन और बागवानी गतिविधियों के उभरते योगदान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे यह मूल्यांकन करने में मदद मिलती है कि क्या मौजूदा हस्तक्षेप केवल अल्पकालिक राहत प्रदान कर रहे हैं या स्थायी आजीविका सृजन में योगदान दे रहे हैं। अध्ययन की कुछ सीमाओं को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। द्वितीयक डेटा पर निर्भरता कुछ मामलों में सूक्ष्म-स्तरीय घरेलू विश्लेषण को प्रतिबंधित करती है, और प्रवासन की गतिशील प्रकृति सटीक माप को कठिन बना देती है। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी इलाके अंतर-जिला असमानताएं पैदा करते हैं जिन्हें हमेशा समग्र आंकड़ों में पूरी तरह से शामिल नहीं किया जा सकता है। इन सीमाओं के बावजूद, यह पद्धति टिहरी जिले में ग्रामीण गरीबों के बीच रोजगार की स्थिति की एक मजबूत वृहद स्तर की समझ प्रदान करती है और नीति-उन्मुख सिफारिशों के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है।

परिणाम

टिहरी गढ़वाल जिले में ग्रामीण गरीबों के बीच रोजगार के अवसरों के विश्लेषण से संरचनात्मक रूप से बाधित श्रम बाजार का पता चलता है, जो कृषि पर उच्च निर्भरता, महत्वपूर्ण मौसमी अल्परोजगार और लगातार बाहरी प्रवासन की विशेषता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने आंशिक राहत प्रदान की है, लेकिन उनका प्रभाव ब्लॉकों और सामाजिक समूहों पर असमान बना हुआ है। निम्नलिखित तालिकाएँ संकलित द्वितीयक डेटा और सांकेतिक क्षेत्र पैटर्न के आधार पर मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1: ग्रामीण परिवारों का व्यावसायिक वितरण

व्यवसाय श्रेणी	परिवारों का प्रतिशत
कृषि (स्व-खेती)	52%
कृषि श्रमिक	14%
मनरेगा मजदूरी कार्य	12%
गैर-कृषि स्थानीय कार्य	9%
प्रवासी प्रेषण-आधारित	13%
कुल	100%

तालिका 1 से पता चलता है कि टिहरी में आधे से अधिक (52%) ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से स्व-खेती पर निर्भर हैं, जो निर्वाह कृषि के निरंतर प्रभुत्व की पुष्टि करता है। हालाँकि, प्रवासी प्रेषण (13%) और मनरेगा कार्य (12%) पर निर्भर परिवारों की अपेक्षाकृत उच्च हिस्सेदारी अपर्याप्त स्थानीय आजीविका अवशोषण का संकेत देती है। गैर-कृषि स्थानीय कार्यों में लगा छोटा हिस्सा (9%) पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमजोर विविधीकरण को दर्शाता है।

तालिका 2: ग्रामीण श्रमिकों के बीच रोजगार की प्रकृति

रोजगार के प्रकार	श्रमिकों का प्रतिशत
पूर्णकालिक रोजगार	28%
मौसमी रोजगार	46%
आकस्मिक/अनियमित कार्य	26%
कुल	100%

आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 28 % ग्रामीण श्रमिकों के पास पूर्णकालिक रोजगार है, जबकि एक बड़ा हिस्सा मौसमी (46%) या आकस्मिक काम (26%) पर निर्भर है। यह अल्परोजगारी और आय अस्थिरता की व्यापकता को उजागर करता है। मौसमी रोजगार बड़े पैमाने पर कृषि और अल्पकालिक सार्वजनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका की भेद्यता को मजबूत करता है।

तालिका 3: ग्रामीण परिवारों का प्रवासन पैटर्न

प्रवासन स्थिति	परिवारों का प्रतिशत
कोई प्रवास नहीं	41%
मौसमी प्रवास	37%
स्थायी/दीर्घकालिक प्रवासन	22%

कुल	100%
------------	-------------

तालिका 3 से पता चलता है कि 59% घरों में कम से कम एक प्रवासी सदस्य (मौसमी स्थायी) है। मौसमी प्रवास (37%) स्थायी प्रवास (22%) की तुलना में अधिक आम है, जिससे पता चलता है कि कई परिवार अभी भी जिले के बाहर पूरक आय की तलाश करते हुए अपने मूल गांवों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। उच्च प्रवासन घटनाएं पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था की सीमित क्षमता की पुष्टि करती हैं।

तालिका 4: मनरेगा में भागीदारी

सूचक	कीमत
मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवार	68%
परिवारों को काम मिल रहा है	49%
100 दिन पूरे करने वाले परिवार	11%
प्रति परिवार काम के औसत दिन	42 days

हालाँकि परिवारों का एक उच्च अनुपात (68%) मनरेगा के तहत पंजीकृत है, केवल 49 को वास्तव में रोजगार मिला, और केवल 11 % ने पूरे 100 दिनों की गारंटी वाला काम हासिल किया। 42% कार्यदिवसों का औसत आंशिक कार्यान्वयन को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह टिहरी जिले में अपनी रोजगार गारंटी क्षमता को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है।

तालिका 5: ग्रामीण गरीबों के बीच उभरती आजीविका गतिविधियाँ

गतिविधि	घरेलू भागीदारी
बागवानी/सब्जियाँ	21%
पशुधन और डेयरी	33%
पर्यटन संबंधी कार्य	8%
स्वयं सहायता समूह उद्यम	18%
कोई विविधीकरण नहीं (केवल कृषि)	20%
कुल	100%

तालिका क्रमिक लेकिन असमान आजीविका विविधीकरण को दर्शाती है। पशुधन और डेयरी (33%) सबसे आम पूरक गतिविधि बनी हुई है, जो पारंपरिक मुकाबला रणनीतियों को दर्शाती है। बागवानी भागीदारी (21%) उच्च मूल्य वाली फसलों को मध्यम रूप से अपनाने को दर्शाती है। हालाँकि, टिहरी बांध जलाशय की उपस्थिति के बावजूद पर्यटन से संबंधित रोजगार (8%) सीमित है। विशेष रूप से, 20% परिवार अभी भी पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, जो दर्शाता है कि ग्रामीण गरीबों के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने अभी तक विविधीकरण के अवसरों तक पहुंच नहीं बनाई है। परिणाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि टिहरी जिले में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के अवसर संरचनात्मक, भौगोलिक और संस्थागत कारकों से बाधित हैं। कृषि का दबदबा कायम है लेकिन यह अपर्याप्त आय सुरक्षा प्रदान करता है। प्रवासन एक प्रमुख आजीविका प्रबंधन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जबकि सरकारी कार्यक्रम आंशिक लेकिन अपर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। बागवानी और पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्र आशाजनक

हैं लेकिन अभी तक व्यापक-आधारित समावेशन हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए स्थायी ग्रामीण आजीविका विकास के लिए एक पर्वत-विशिष्ट, एकीकृत रोजगार रणनीति आवश्यक है।

निष्कर्ष

टिहरी गढ़वाल जिले में ग्रामीण गरीबों के बीच रोजगार के अवसरों पर वर्तमान अध्ययन पर्वतीय ग्रामीण समाजों में आजीविका की बाधाओं की गहरी संरचनात्मक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्रमिक विकासात्मक हस्तक्षेपों के बावजूद, जिले को एक संकीर्ण और नाजुक रोजगार आधार का सामना करना पड़ रहा है। निर्वाह कृषि प्रमुख व्यवसाय बनी हुई है, फिर भी इसकी घटती उत्पादकता और मौसमी चरित्र ने ग्रामीण परिवारों को बनाए रखने की इसकी क्षमता को काफी कम कर दिया है। परिणामस्वरूप, अल्परोजगारी और आय असुरक्षा व्यापक बनी हुई है। ग्रामीण परिवारों के एक बड़े हिस्से के लिए प्रवासन एक केंद्रीय मुकाबला तंत्र के रूप में उभरा है। जबकि प्रेषण घरेलू उपभोग और शिक्षा में सकारात्मक योगदान देता है, कामकाजी उम्र की आबादी का निरंतर बहिर्वाह स्थानीय अर्थव्यवस्था की सीमित अवशोषण क्षमता को दर्शाता है। कृषि का नारीकरण और पहाड़ी गांवों में बढ़ता जनसांख्यिकीय असंतुलन संकट-प्रेरित प्रवासन की सामाजिक लागत को और अधिक रेखांकित करता है। इन रुझानों से पता चलता है कि पर्याप्त स्थानीय रोजगार सृजन के बिना, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी का हास जारी रह सकता है। सरकारी हस्तक्षेप, विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और स्वयं सहायता समूह-आधारित आजीविका पहल ने पूरक मजदूरी रोजगार और मामूली आय विविधीकरण प्रदान करके एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक भूमिका निभाई है। हालाँकि, उनका प्रभाव काफी हद तक अल्पकालिक और असमान रहा है। सीमित कार्यदिवस, कार्यान्वयन अंतराल, कमजोर बाजार संपर्क और दीर्घकालिक विकास योजना के साथ अपर्याप्त अभिसरण ने इन कार्यक्रमों को ग्रामीण रोजगार के परिवर्तनकारी इंजन बनने से रोक दिया है। साथ ही, अध्ययन में टिहरी बांध जलाशय से जुड़े बागवानी, पशुधन विकास, ग्रामीण उद्यमिता और पर्यटन में उभरते लेकिन कम उपयोग किए गए अवसरों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में पहाड़-अनुकूल तरीके से रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, मूल्य-श्रृंखला एकीकरण, संस्थागत ऋण पहुंच और दूरदराज के गांवों और कमजोर समूहों के लिए लक्षित समर्थन की आवश्यकता है। निष्कर्षतः, टिहरी में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार के लिए एक समान मैदान-उन्मुख दृष्टिकोण के बजाय एक संदर्भ-संवेदनशील, पर्वत-विशिष्ट विकास रणनीति की आवश्यकता है। नीतियों को कृषि-विविधीकरण, पर्यावरण-पर्यटन संवर्धन, ग्रामीण उद्यम विकास और मानव पूंजी वृद्धि के माध्यम से स्थायी आजीविका सृजन की दिशा में अल्पकालिक वेतन समर्थन से आगे बढ़ना चाहिए। स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और प्रभावी कार्यक्रम अभिसरण सुनिश्चित करना संकटपूर्ण प्रवासन को कम करने और हिमालयी क्षेत्र में समावेशी, लचीला ग्रामीण विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ

1. भारत की जनगणना। (2011). डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। ऑफिस ऑफ़ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, भारत सरकार।

2. भारत सरकार। (2005). महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2005। मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट।
3. भारत सरकार। (2023). MGNREGA एनुअल रिपोर्ट 2022-23। मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट।
4. उत्तराखंड सरकार। (2020). उत्तराखंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। प्लानिंग डिपार्टमेंट, उत्तराखंड सरकार।
5. रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। (2022). दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (DAY-NRLM) फ्रेमवर्क। भारत सरकार।
6. NITI आयोग। (2018). स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75। भारत सरकार।
7. प्लानिंग कमीशन। (2013). हिल एरिया के डेवलपमेंट पर कमीटी की रिपोर्ट। भारत सरकार।
8. सिंह, आर., और कौर, पी. (2019). हिमालयी क्षेत्रों में ग्रामीण पलायन और आजीविका की चुनौतियाँ: उत्तराखंड से सबूत। जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, 38(3), 421-438.
9. श्रीवास्तव, आर. (2020). भारत में माइग्रेशन और ग्रामीण लेबर मार्केट: उभरते पैटर्न और पॉलिसी चुनौतियाँ। इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स, 63(1), 1-21.
10. उत्तराखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। (2021). एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार।